RAJYA SABHA

Thursday, the 23rd August, 1990
1 Bhadra, 1912 (Saka)

The House met at eleven of the the clock, **Mr. Chairman** in the chair.

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Export of Raw Jute

*201. SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Will the Minister of TEXTILES be pleased to state:

(a) whether government have formulated any scheme for the export of raw jute; and

(b) if so, what are the details in this regard ?

वस्त्र मंत्री साथ में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार (श्री शरद यादव): (क) और (ख) सरकार ने फ़सल की मात्रा को ध्यान में रखते हुए तथा कच्चे पटसन के उद्योग को स्थिरता प्रदान करने के उद्देश्य से वर्ष 1990-91 के दौरान कच्चे पटसन के निर्यात की अनुमति देने का निर्णय लिया है। फ़िर भी वास्तविक निर्यात की अनुमति बाजार की स्थिति को ध्यान में रखते हुए ही दी जाएगी।

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Mr. Chairman, Sir, the point is, the hon. Minister says that the Government have decided to exp rt. Then, the Minister says that the size of the export will be decided by the Government later on an estimate of the crop.

My first supplementary to the Minister is, why have the Government so decided, that they would permit export ? Why have the Government decided ? I ask this question because everybody knows that we had an extremely short crop last year. There was speculation in jute prices, a number of jute mills were closed and thousands of worker is thrown out of their jobs. The main reason for this was the shortfall in production last year. Also, the price of the finished product was too uneconomical in the national and international markets. This being the experience, why have the Government decided to export ? According to my information, the jute crop will be...

MR. CHAIRMAN: He has said here 'size of the crop'.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: That is secondary.

MR. CHAIRMAN: He says that he has decided on the basis of the size of the crop. He has estimated that the crop is good.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Let me argue my case.

MR. CHAIRMAN: The Question Hour is not for argument. It is only for putting questions and getting answers. Please put your supplementary.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: My question is, why have the Government decided to export? The reply should have been 'Government will take a decision on the question of export...

MR. CHAIRMAN: Please put your question.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Sir, please let me finish. If it was the intention of the Government, the reply should have been 'Government will decide on the question of export after having made a final estimate about the availability of the crop'. But he just says that they have decided to export. I am asking, why ?

MR. CHAIRMAN: Is that a mistake, according to you?

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: My supplementary is this. The Government say that they have decided to export. I would like to ask, in view of the fact that there was a shortfall in production last year and in view also of the fact that the market condition was bad, which resulted in closure and retrenchment, why does not the Government think of building up a large buffer stock because jute is a non-perishable crop ? When you can build up a buffer stock in the case of foodgrains, why should there not be a buffer stock in respect of jute, for the coming season, to tide over the crisis in the market?

MR. CHAIRMAN: His question is, 'why don't you think of building up a buffer stock in the case of jute'?

श्री शरद यादव : माननीय सदस्य श्री गुरुदास दासगुप्त जी को बहुत धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस सवाल को पूछा है । इस बार जूट की जो क्राप है वह 92 लाख बेल्स होने वाली हैं और कैरोओवर जो हमारा स्टाक है । वह 14 लाख बेल्स है । एस्टीमेट है कि 102 बेल्स हमारे पास होंगे । हमारे डोमेस्टिक कंजम्शन के लिये 82 लाख बेल्स की जरुरत पड़ेगी । मैं गुरुदास दासगुप्त जी से कहना चाहता हूं कि जो नार्थ-ईस्ट, है, उसकी जो मेजर एक्टिविटी है वह जूट पर निर्भर करती है ।

लेकिन उन्होंने एक पक्ष का जिक्र किया कि कारखाने बंद हो जाते हैं, मजदूर तंग रहते हैं । लेकिन इस जूट उद्योग में सबसे बड़ी आबादी, सबसे बड़ी संख्या किसानों की है । 40 लाख किसान इसमें लगे हुए हैं । 40 लाख के ऊपर निर्भर लोग होंगे तो डेढ़-दो करोड़ लोग हो जाते हैं । इन लोगों को यदि हम इंडस्ट्री का अंग नहीं मानेंगे तो जिस तरह से यह इंडस्ट्री क्राइसिस में चलती रही है उसी तरह आगे भी चलेगी । इस बात का मैं इसलिए जिक्र करना चाहता हूं कि जब काटन का क्राप इस देश में आधा तो हिन्दुस्तान भर के मिल सेक्टर ने हैंडलूम वीवर्स ने और पावरलूम वीवर्स ने कहा कि काटन का एक्सपोर्ट नहीं करना चाहिए मैंने उस समय भी मजबूती से पार्लियामेंट में कहा था कि हिंदुस्तान का जो टेक्सटाइल डिपार्टमेंट है उसकी यह पक्की मान्यता है कि इस टेक्सटाइल डिपार्टमेंट का सबसे बेहतरीन हिस्सा कोई है तो किसान है जो काटन ग्रो करता है । मैं आज भी कहना चाहता हूं कि जूट ग्रोवर किसान है उसको प्रोटेक्ट करना मैं अपनी सरकार का फ़र्ज मानता हूं और और जिस तरह से स्पेकुलेशन है जिस तरह से कालाबाजारी चलती है इसमें इस बार मैं दो बार कलकत्ता में मीटिंग करके आया हूं जे.सी.आई. से, बड़े पैमाने पर जो भी हमारी कूवत होगी हम करेंगे लेकिन तत्काल तो सारा स्ट्रक्चर ठीक नहीं हो सकता है । कई दिनों का बिगड़ा हुआ मामला हैं, उसको हम बहुत तैयारी के साथ ठीक करना चाहते हैं । गोदामों को बनाने का हमारा काम स्टेट गार्नमेंट के साथ परसुएशन करके चल रहा है ।

श्री सभापति : बफ़र स्टाक ?

श्री शरद यादव : जे.सी. आई. को बहुत एक्टिवाइज कर रहे हैं लेकिन जूट में स्पेकुलेशन जो हैं यह इस उद्योग को तबाह किये हुए हैं । तो उद्योग के लिए भी हमने बहुत से मेजर्स उठाये हैं यानी जूट के डाइवर्सीफिकेशन के प्रोग्राम बहुत बड़े पैमाने पर चले हुए हैं । हमारा प्रोग्राम है कि हम जूट से कागज बनाने का काम करें । इस प्रोजेक्ट पर मैं लगा हुआ हूं और शायद यह देश की सबसे बड़ी जरुरत है ... (व्यवधान)... मैं उसी बात पर आ रहा हूं ।

MR. CHAIRMAN: For buffer stock?

श्री शरद यादव : मैंने इस बार जे.सी.आई. से कहा है कि एक साथ सालाना आर्डर मत दो, लगातार आर्डर

दो मिलों को । गुरुदास जी ने जो बात कही उसको मैं मानता हूं कि इस ढंग से मिलें बंद होती हैं और मजदूर तंग होते हैं । इसको हम सुधारना हैं । लेकिन जो कलकत्ता और उस पूरे इलाके में स्पेकुलेशन का काम चलता है तो भी सरकार जूट ग्रोअर्स के लिए दाम गिरने नहीं देगी और मैं पक्की तौर पर कहता हूं कि जिस तरह से काटन में एक्सपोर्ट किया; महीने में 15 दिन में 12 दिन में इसी तरह से जूट का भी एक्सपोर्ट किया जाएगा और यहां के मारकेट में कोई कमी नहीं होने दी जाएगी तथा इसके दाम को मिनिमम प्राइस से कभी नीचे नहीं गिरने दिया जाएगा, कामर्शियल प्राइस पर उस दाम को हम रखने की कोशिश करेंगे । जट हमारे पास 5-7 लाख बेल सरप्लस है, हम पूरी दुनिया के मारकेट में जाकर वह बहतर दाम में बिक सके इसका भी इंतजाम करेंगे । स्टाक को बाकायदा बनाकर रखेंगे जिससे कि जो जमाखोर हैं जो स्पेकुलेटर्स हैं इस जूट के धंधे में उनको हम दबा सकें । हम लाखों किसानों को बरबादी के करार पर जाने से रोकेंगे और उसके जो भी उपाय हो सकते हैं वे जरुर करेंगे । हमारी किताब में, हमारे सिद्धांत में किसान और मजदूर दोनों बराबर चीजें हैं, दोनों को बराबर मजबूती से खड़ा करने का काम करेंगे तभी दौड़ हो सकती है ।

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Sir, the reply of the Minister only strenghens my point. Let me ask the Minister why the Government does not desire to export finished jute goods instead of exporting raw jute. Why do they not decide to export finished value-added jute goods ?

MR. CHAIRMAN: He has answered it. The House is very well informed now.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: This is (a). (b) part of my question is this. The Government must be aware of serious undercutting in the international market both in regard to raw jute and finished goods. It is being done by some of our neighbours. I do not what to name them. Sir, my second supplementary is this. Shall the Government of India take a lead in building up a conscience among the jute-producing countries so that under-cutting is not resorted to. Why will the Government not export finished raw jute goods instead of raw jute?

MR. CHAIRMAN: Why don't you export value-added goods and why don't you have talks with the neighbouring countries.

श्री शरद यादव: सभापति महोदय, माननीय सदस्य श्री गुरुदास दासगुप्त जी ने जो कहा है कि वेल्यु ऐडड फ़िनिशड गुड्ज़ बेचने में ज्यादा फ़ायदा है लेकिन इस काम के लिए हमारे पास मजबूत इनफ्रास्ट्रक्चर और पूरी तैयारी होनी चाहिये । वह तैयारी हमारी... (**व्यवधान**)

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: 14 jute mills are closed in West Bengal. The Central Government can take the decision to re-open the jute mills. The State Government cannot. If the jute mills are re-opened, we can boost up the production of jute goods and that may enable us to export. And the Government has not been taking the decision on that.

श्री शरद यादव : सभापति महोदय, जब मिल बन्द होती है तो उसको खोलने के लिए बहुत लोग लगते हैं, फ़ाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी लगते हैं । आज जब फ़सल आई हुई है तब तत्काल यह सब काम कर के रेडी कर के नहीं दे सकता, यह मेरी कुव्वत के बाहर काम है । मेरी कुव्वत में एक काम है कि मैं किसान द्वारा पैदा की जाने वाली जूट के दाम न गिरने दूं । उसके जो उपाय हो सकते हैं और जिस तरह से भी हो सकता है वह हम कर रहे हैं । आज तैयारी हमारी नहीं है कि फ़िनिशड गुड्ज़ का एक्सपोर्ट करें । एक्सपोर्ट हमारी जूट का

बहुत है लेकिन जितना होना चाहिये उतना नहीं है । हमारा जूट का डाइवर्सीफ़िकेशन प्रोग्राम है और जूट का बाकी सामान पैदा कर के एक्सपोर्ट करने की आज हमारी उतनी तैयारी नहीं हैं कि हम किसान द्वारा पैदा की हुई जूट की वैल्यू एडेड फ़िनिशिड आइटम्स का एक्सपोर्ट कर सकें । इसलिए आज की जो परिस्थिति है उस में जो बेस्ट किया जा सकता है उसमें एक्सपोर्ट करना मैं वाजिब मानता हूं और इस थ्रेट को इस्तेमाल किया जाएगा और इससे कोई जूट बिजनेस पर जूट इंडस्ट्री पर कोई असर नहीं पड़ेगा इतना मैं वायदा करता हूं ।

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: What about under-cutting?

श्री सभापति : उनके प्रश्न का एक पोर्शन था कि पड़ोसी देशों से आप वार्तालाप कर के ताकि अंडर-कटिंग न हो इसको क्या आप देखेंगे ?

श्री शरद यादव : सभापति जी, इसकी बात चल रही है कि किस तरह से ठीक हो सकता है । इस पर हम लोग लगे हुए हैं ।

श्री सभापति : बंगलादेश से अपनी एक कमेटी है न ।

श्री शरद यादव : हो सकता है ठीक हो जाए । हम लोग दोनों मिल कर करेंगे ।

श्री सन्तोष बागडोदिया : सभापति महोदय मंत्री महोदय ने जो बहुत जोर-शोर से यह बताने की चेष्टा की कि यह एक्सपोर्ट करना बहुत जरूरी है, पहले तो उनकी खबर बहुत गलत है । मेरी समझ में यह 92 लाख वेल्स जो बता रहे हैं यह 85–90 लाख वेल्स से ऊपर नहीं जा सकता है । यह जो कंजम्पशन 92 लाख बेल्स का बताया है मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या क्या है । मिलों के कंजम्पशन के इलावा और भी चीजों में कंजम्पशन होता है । काफी जूट घरों में सफाई के काम में भी आता है । सारा मिला करके आप देखेंगे कि हिन्दुस्तान में कंजम्पशन 90 लाख बेल्स का हो जाएगा । जैसे गुरुदास दास गुप्त जी ने बताया कि 14 मिलें बन्द हैं, मेरा कहना यह है कि 14 नहीं बल्कि 17 मिलें बन्द पड़ी हुई हैं । मिलें जो बन्द पड़ी हुई हैं इन से करीब ढाई तीन लाख लोग प्रभावित हैं । मैं यह नहीं कहता कि आप फारमर्ज़ का इंट्रेस्ट न देखें लेकिन आप एक तरफ ही ध्यान दें और दूसरी तरफ ध्यान बन्द हो जाए, ऐसा निर्णय नहीं होना चाहिये कि जिससे जूट इंडस्ट्री बिलकुल खत्म हो जाए । एक तरफ आप बात कर रहे हैं एग्रो बेस्ट इंडस्ट्री की और दूसरी तरफ आप जूट इंडस्ट्री को ..(व्यवधान)

श्री सभापति : आपका प्रश्न क्या है ?

श्री सन्तोष बागड़ोदिया : मैं नहीं बता रहा हूं ।

श्री सभापति : पूछिए । बताने का काम मंत्री का है । पूछने का काम आपका है ।

श्री सन्तोष बागड़ोदिया : 1984 में 124 मिलियन बेल्स हुई थी तब आपने कितना एक्सपोर्ट किया था, उसमें क्या गड़बड़ी हुई थी ? जबसे आपने सालाना आर्डर दिया है, हर महीने माल लिया जाएगा, तब से डी०जी०एम०ए०डी० ने हर महीने कितना माल लिया है या खाली आर्डर आपकी फाइल में पड़ा हुआ है ? आप जो कह रहे हैं इतनी जल्दी मिल ओपन नहीं हो सकती है मैं यह बताना चाहता हूं कि अगर आप चेष्टा करें तो यह 17 की 17 मिलें कल से चालू हो सकती हैं । जूट मिल का ढर्रा ऐसा है कि एक दिन बन्द होती है और एक दिन में चालू होती है । चलाने में कोई देशी असुविधा वाली बात नहीं है। आप कहते हैं कि जितना माल मिनिमम प्राइस में आफर होगा वह जे०सी०आई० ले सकते हैं, आप ले सकते हैं । आपका इनफ्रास्ट्रक्चर पांच या दस वर्ष पुराना

है । आप क्यों नहीं सारा माल ले सकते हैं । यह कहना वह गड़बड़ करते हैं वह गड़बड़ करते हैं, हम एक्सपोर्ट करते हैं, पता नहीं किस कारण से आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं । मुझे तो इसका कोई औचित्य नज़र नहीं आता है ।

श्री सभापति : वह पूछ रहे हैं क्या आप इनकी मदद ले कर परसों मिलें चलाने के लिए तैयार हैं । बागड़ोदिवा जी की मदद ले लीजिये, परसों मिलें चलवा दीजिये ।

श्री शरद यादव : मैं उनकी राय से सहमत हूं कि 92 लाख बेल्स भी डोमेस्टिक कन्जम्पशन हो, वैसे 78 लाख बेल्स मिल्स में और मिसलेनियस चीजों में 4 लाख, बेल्स लगेंगी लेकिन आपकी राय में मान लेता हूं । इसके बाद भी हमारे पास दो तीन लाख बैल्स सरप्लस होंगी जिसको हम एक्सपोर्ट करेंगे और जैसे इन्होंने कहा कि 14 मिलें खुल सकती हैं, इनके पास ऐसा कोई फारमूला है तो (**व्यवधान**) इन्होंने दो तीन बार कहा है लेकिन आज तक मेरे पास आए नहीं हैं । आज भी यही कह रहे हैं ।

श्री सन्तोष बागडोदिया : इनके सेक्रेटरी को चार बार मैंने नाम लिखाया, पर वापिस कोई जवाब नहीं आया । ।

श्री शरद यादव : फोन पर किया होगा । मेरी आदत तो इनसे सीधी यही बात करने की है ।

श्री सभापति : हां, तो यही मैंने आपकी आदत को जानते हुए कहा कि यहां पर बाहर जाकर बात कर लेना ।

श्री शरद यादव : तो इन्होंने जो बातें कहीं हैं, वह काफी उत्साहजनक हैं । मेरी समझ नहीं आ रही, यदि इनके साथ बैठ करके, चूंकि यह जूट के धंधे में है, हो सकता है कि इनके पास जरा थोड़ी सी मुझसे ज्यादा जानकारी हो । तो वह जो बतायेंगे, मैं उस पर काम करूंगा और यदि बेहतर हो सकता है तो .....

श्री सभापति : बस ठीक है । तो आप इनसे बात कर लीजिए ।

श्री शरद यादव : और जो जे०सी० आई० के आदेश का कहा, तो वह चार दिन पहले हमारा आर्डर चला गया है कि दो महीने के लिए और... (**व्यवधान**)

SHRI DIPEN GHOSH: Sir, you have understood, I suppose, that if the Minister and Mr. Bagrodia unite, the mills could be opened?

MR. CHAIRMAN: I do not know. He said it. I have only communicated it.

श्रीमती कमला सिन्हा : सभापति जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहती हूं–मंत्री जी ने आपने जवाब में कहा... (**व्यवधान**)

श्री सन्तोष बागड़ोदिया : आंध्र में जूट है ।

श्री सभापति : गुंटूर में कोई जूट नहीं होता । गुंटूर में नहीं है ।

श्री कमला सिन्हा : मंत्री जी ने अपने जवाब में कहा कि इस देश में चालीस लाख किसान हैं, जो पटुवा पैदा करते है, जूट ग्रोयर्ज ।

दूसरी बात, उन्होंने कहा कि हम मजदूरों का नुकसान नहीं होने देंगे और हम कल-कारखानों को भी चलायेंगे । तो मैं यह जानना चाहत हूं, चूंकि बिहार में जूट की खेती होती है, और.... (**व्यवधान**)

श्री सभापति : उन्होंने यह भी कहा कि किसान का नुकसान न हो, यह भी देखेंगे ।

श्रीमती कमला सिन्हा : जी हां, मैं इसी पर कहना चाहता हूं कि जैसे गेहूं के लिए एक सपोर्ट प्राईस सरकार ने तय किया हुआ है, क्या जूट के लिए सरकार इस तरह की एक सपोर्ट प्राईस तय करेगी, क्योंकि होता यह है कि जिस साल जूट का उत्पादन कम हो, तो बाजार भाव बढ़ जाता है और ज्यादा दाम में बिकता

आपको बताना चाहती हूं । हम लोगों ने पूर्णिया और कटिहार जिलों में आंदोलन किया, जूट के ग्रोअर्ज ने आंदोलन किया कि हमारी जूट का क्या होगा ? लोगों ने कहा कि जितना एक किलो जूट पैदा करने में जो खर्चा बैठेगा, वह साढ़े चार रुपये और जे सी०आई० ने जो रखा है, वह पौने दो सौ रुपये का, तो किसानों ने कहा कि हम तो जला डालेंगे, जलावन बनायेंगे वह ज्यादा अच्छा है, बनिस्बत बेचने के ।

तो मेरा सवाल तो यह है कि ... (व्यवधान)

श्री सभापति : नहीं , सपोर्ट प्राईस का आपका सवाल है ।

श्रीमती कमला सिन्हा : यह किसानों के लिए सपोर्ट प्राईस तय करेंगे कि नहीं?

मेरा दूसरा सवाल यह कि .... (व्यवधान)

श्री सभापति : आप बहुत से सवाल मत कीजिए ।

श्रीमती कमला सिन्हा : जूट के कारखानों में काम करने वाले लोग--जो कारखाने बंद पड़े हैं, आज हमारे प्रांत में भी कई कारखाने बंद पड़े हुए हैं, प्रांतीय सरकार चला नहीं सकती ।

तो मैं यह जानना चाहती हूं कि केन्द्र सरकार क्या उनको अपने हाथ में लेकर चलाने का प्रबंध करेगी, क्योंकि शरद यादव जी ने कहा कि हम किसानों और मजदूरों दोनों को बराबर रक्षण देना चाहते हैं ।

श्री सभापति : आपकी बात ठीक है।

श्रीमती कमला सिन्हा : मेरे तीन प्रश्न हैं । तीसरा प्रश्न मैं यह पूछना चाहती हूं कि ... (व्यवधान)

श्री सभापति : सप्लीमेंट्री एक होता है, सब-सेक्शन हो जाते हैं, लेकिन आपने तो तीन-तीन चार-चार क्वेश्चन रखे ।

श्रीमती कमला सिन्हा : मेरा तीसरा प्रश्न यह है कि कि आज रा-जूट अगर विदेश में एक्सपोर्ट करेंगे, तो उसकी कीमत जो हमें मिलेगी, वह शायद उतनी नहीं मिलेगी, क्योंकि बाजार में जूट के सब्सिट्यूट आज आ गये हैं । जूट पेरिशेबल गुड है ।

श्री सभापति : यह तो वह जानते हैं । आप प्रश्न कीजिए ।

श्रीमती कमला सिन्हा : तो, मैं यह जानना चाहती हूं कि जूट का डाइवर्सिफिकेशन, जैसे गुरुदास दासगुप्त जी ने कहा कि वैल्यु ऐडिड प्राडक्ट बनाकर अगर हम एक्सपोर्ट करे, तो हमें फारेन एक्सचेंज भी ज्यादा मिलेगा तो इन तीन सवालों का जवाब मैं, मंत्री जी से चाहती हूं ।

श्री सभापति : तीसरे का जवाब तो आप दे चुके हैं ।

श्री शरद यादव : इसका जवाब मैं दे चुका हूं, सिर्फ माननीय सदस्या ने जो पूछा है .... (व्यवधान)

श्री सभापति : सपोर्ट प्राईस।

श्री शरद यादव : जूट की मिनिमम प्राईस जो है, वह पिछले साल से अधिक हमने रखी है । टी०डी०-5 में 340 रुपये रखी है और पिछली बार जो थी, वह 280-262 रुपये थी । तो बहुत बड़े दाम को बढ़ा करके हमने जूट के मिनिमम प्राईस का तय किया हुआ है और मिनिमम प्राईस पर अभी भी 150, 200 या 250 रुपये के ऊपर चल रहा है ।

रहा सवाल, उन्होंने मिल के बारे में कहा, तो मैंने कहा ना अब यह तो यक्ष प्रश्न है--जूट में हो, टैक्सटाईल में हो, यह कैसे बिलकुल ठीक हो, दुरुस्त हो, अभी तो इस सवाल से यह सवाल उठता नहीं है लंबा सवाल है, इसका लंबा

जवाब है । मैं इतना ही कहना चाहता हूं जो माननीय सदस्या ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस का कहा है, कि हम जे.सी.आई. के जरिए उससे नीचे प्राइस गिरने नहीं देंगे और किसानों का जूट जले नहीं इसका भी इंतजाम जरूर करेंगे । एक्सपोर्ट का जो उन्होंने कहा तो हमारी पालिसी में यह है कि एक्सपोर्ट तब करेंगे जब अच्छे मिल रहे होंगे ।

श्री सभापति : जब अच्छे पैसे मिलेंगे ।

DR. YELAMANCHILI SIVAJI: How does the Government propose to protect the growers as well as jute industry from the onslaught of the imported artificial fibre, high density propylene and other man-made fibre and bags made of that fibre?

श्री शरद यादव : सभापति महोदय, इसमें तो यह सवाल उठता नहीं है, लेकिन हमारा तो मैन मेन फाइवर से जो बैग्ज़ बनते हैं उसमें एफ.सी आई. और तमाम जो स्टेट कार्पोरेशन्ज हैं उनको सबको कंप्लसरी जूट बैग लेने पड़ते हैं और उसके नियम बने हुए हैं और जो आपने कहा है तो प्रोटैक्शन अपने आप मिला हुआ है और उस पर हम काम लोग करते रहते हैं ।

Violation of customs Rules by Aparna Ashram of Shri Dhirendra Brahmchari

*202. SHRI SUKOMAL SEN: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to an article in the Illustrated Weekly of India of 3rd June, 1990 issue, to the effect that Aparna Ashram of Shri Dhirendra Brahmchari was given customs duty exemption for the import of a Telemetric Polygraph System from Japan;

(b) whether Government are awar that instead of importing this medical equipment Aparna Ashram has imported studio equipment for commercial use; and

(c) if so, what action Government have taken or proposed to take against Aparna Ashram for the infringement of provisions of Customs Act ?

THE FINANCE MINISTER (PROF. MADHU DANDAVATE): (a) Yes, Sir.

(b) and (c) Enquiries are being made to ascertain the facts regarding the allegations contained in the said article in the Illustrated Weekly in this regard.

SHRI SUKOMAL SEN: Sir, our Minister's reply is quite strange. I do not know why the Government has to ascertain the fact only after the things came in the Illustrated Weekly. Things are happening since 1981. It is not a recent case. It started in 1981 Everybody knows that Brahmchari once was having a political favour at the highest level.

MR. CHAIRMAN: You question is why they did not tak cognizance before the article appeared in the "Illustrated Weekly." Is that your question? You come to your question quickly. Otherwise you will ask three questions.

AN HON. MEMBER: This is part (a) of the question.

SHRI DINESH GOSWAMI: It is better if he formulates the question from now on.

SHRI SUKOMAL SEN: The Brahmachari applied to ICMF for income-tax exemption for impo